

Monetization of BSNL assets

Through D.O. letter the Secretary Department of Telecom have published a list of 54 pages and enlisted 531 locations of BSNL land parcels, buildings, staff quarters, Telecom Training, centers etc. for monetization. The Secretary DOT has also writes a letter to all the Chief Secretaries the states throughout the country to come forward and take initiative if the Govt. wants to purchase any assets of the BSNL listed for monetization in the state concern. Monetization is a process of revenue generation through sell of the assets, materials etc. It is a shocking news for all the BSNL stake holders and for the people of the nation as all these assets have been procured by the money paid to the Govt. through different type of Taxes. It will not be out of context that a good number of properties, land parcels, buildings, staff quarters have been procured and build up by the BSNL by its own earnings after its formation. We are living in a democratic country and a Govt. elected by the people is not expected to do any unfair action towards the people. It is known that several PSUs were in existence at the time of conversion of Department of Telecom operation and Telecom services in a corporation namely "Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)". Through the those PSUs were running in a super position with a huge number of well paid executives and non executives employees. So the workers recruited by the Govt. and working in the depart of Telecom were Transferred to be apart of PSUs under the Govt. entity. The workers were worried for their pension as they had worked for several years as Govt. Servants. They were worried that the new entity after conversion as PSUs will survive or not?. They worried about their job security as the political move Indications were coming that the Govt. has decided to corporatize the Telecom services into a corporation and latter it may be pushed to privatization, with these worries and apprehensions the workers went on total strike from 6th of September 2000 and it was a historic day for the workers when the agreement reached between the Govt. and the workers federations that.

(1) The pension of the employees absorbed in the company will be paid under pension rule 1972 and for that one addition in article -37 of the pension rule was inserted. The employees transferred from the department of Telecom operation and Telecom services will opt to be absorbed in Corporation. They will be paid the pension at par with the Govt. employees and for that inserted rule was marked as article 37A. After written agreement with the Govt. which presidential order was published in the gazette of India. The workers believed upon the Govt. commitment and very smooth transfer of workers took place. Under the presidential order issued in that respect it was also committed by the Govt. that all the assets and liabilities of the department of Telecom operation and department of Telecom services will be transferred to the corporation which came in to the existence from 1st October, 2000.

The people of the Nation are in dark that the Govt. has not only deviated from its commitment given through Presidential order at the time of Corporatization rather it just revert the commitment in reverse direction. The buildings at prime locations in each capital cities of the

country have been taken back by the Department. The Telecom centre at Ghaziabad has taken over by DOT in recent past and the voice of the workers were suppressed.

Now the 531 properties of Prime location of metro cities and capital cities of the states have been enlisted and circulated to be sold either to the state Govt. or its PSUs or any Private Corporates.

The stake holders are shocked that they have not been consulted either by the BSNL management or by the Govt. That the revenue generated through sale of the properties will come in the BSNL fund or it will go to the finance Ministry of the Govt. of India. So far the services of the BSNL, is concern most of that has been handed over to private vendors and contractors.

In this changing scenario the apprehensions of the workers at the time of corporatization that the Government is converting the Telecom into a corporation for to privatization is going to be proved now.

In between the BSNL management has signed a MOU with Boston Group of consultant to study about the service condition, involvement of the staff in the streams, customer service centers and to submit report within 8 months. This company has been engaged on payment of Rs. 132 crores which is a very big amount for the BSNL which is still running in difficulties. The right of the workers have been surpasses the 3 wage revision is not implemented, all the promotional aspects have been stopped in half of the circles of BSNL.

All together there is full stalemate on HR issues in the BSNL

In this scenario the unions and associations leaving all their reservations should come at a platform to think over the situation and to reach an united approach to save the interest of the employees of BSNL. We the NFTE is always prepare for any united approach.

**NFTE Zindabad -
Workers Unity Zindabad**

बीएसएनएल की परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण

एक अर्धसरकारी पत्र के अनुलग्नक के रूप में दूरसंचार सचिव भारत सरकार ने 54 पृष्ठों की एक सूची जारी की है जिनमें बीएसएनएल 531 परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध किया गया है। सचिव, दूरसंचार विभाग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को सूचित किया है कि उनके राज्य में स्थित परिसंपत्तियों की जरूरत अगर राज्य सरकार या उनके द्वारा नियंत्रित किसी लोक उपक्रम को है तो वे उसके मौद्रीकरण के माध्यम से स्वामित्व ग्रहण करने हेतु अग्रसर हो सकते हैं। यह स्पष्ट है कि मौद्रीकरण की अर्थ परिसंपत्ति अथवा संसाधन को बिक्री कर राजस्व पैदा करने की प्रक्रिया है।

यह एक अत्यंत चौंकाने वाला समाचार है, जिसमें बीएसएनएल के तमाम भागीदार एवं राष्ट्रीय आवाम के लिए धोखा जैसा है क्योंकि यह परिसंपत्तियां जनता द्वारा भुगतान किये गये विभिन्न प्रकार के करों से प्राप्त राजस्व से ही सरकारी सम्पत्ति बनाई जाती है। दुखद ये है कि ठीक से जांच-पड़ताल करने पर ऐसा पाया जायेगा कि जिन परिसंपत्तियों को मौद्रीकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया है, उनमें से बहुत सारे निगम ने अस्तित्व में आने के बाद कंपनी द्वारा इसके अपनी कमाई से अर्जित की गई है जिनमें भूमि, भवन एवं स्टाफ क्वार्टर शामिल हैं। हम एक लोकतांत्रिक मुल्क में रहते हैं। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार सत्ता में आती है। यह मान्य सत्य है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनहित में कार्य करती है। यह माना जाता है कि लोकतांत्रिक सरकार जन विरोधी कार्य नहीं कर सकती।

यह ज्ञात था कि देश बहुत सारे लोक उपक्रम संचालन में हैं तथा उनके कर्मचारी और अधिकारी अच्छी स्थिति से पूरी नौकरी करने के बाद खुशहाल स्थिति में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस मान्यता के बावजूद जब सरकार ने दूरसंचार संचालन तथा दूरसंचार सेवा विभाग को नियम में परिवर्तित करने का फैसला किया तो दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों में यह भय व्याप्त हुआ कि सरकार पहले विभाग को निगमित करेगी और उसके बाद उसे निजी हाथों को सौंप दिया जायेगा, और इस भय की आशंका को ध्यान में रखकर समस्त कर्मचारियों ने 6 सितंबर 2000 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले गए। देश की संचार व्यवस्था ठप्प पड़ गई और 8 सितंबर 2000 को सरकार एवं कर्मचारी पक्ष का एक समझौता हुआ जिसमें कर्मचारियों की मांगें मानते हुए एक लिखित समझौता हुआ।

समझौतों के आधार पर भारत के गजट में राष्ट्रपतीय आदेश प्रकाशित हुआ जिसके तहत समस्त कर्मचारियों को नवसृजित भारत संचार निगम में विकल्प देकर समाहित होने पर उन्हें भारत के पेंशन अधिनियम 1972 के तहत पेंशन भुगतान किये जायेंगे और इसके लिए नियमों में आंशिक संशोधन भी किया गया और पेंशन अधिनियम के नियम 37 से नियम 37ए लगाई गई, जिसमें दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को बीएसएनएल में समाहित होने पर भारत सरकार के संचित राशि से पेंशन की भुगतान की जायेगी। इसके साथ ही कंपनी को आर्थिक रूप से जीवंत रखने तथा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रखने की लिखित वादा सरकार ने किया। उक्त अवसर पर जारी राष्ट्रपतीय आदेश में यह भी लिखा गया कि बीएसएनएल को अस्तित्व में आने के उपरांत दो विभागों यथा दूरसंचार प्रचालन एवं दूरसंचार संवाएं विभाग की समस्त परिसंपत्तियां और देयकों को बीएसएनएल के स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

परंतु ऐसा करने के उपरांत सरकार ने पहले तो प्रत्येक राज्यों की राजधानी में स्थिति प्रमुख भवनों को एकतरफा आदेश ने हस्तगत कर दिया और शनैःशनैः कई भवनों, दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्रों आदि पर कब्जा जमा लिया। अभी कुछ माह पूर्व एलटीटीसी गाजियाबाद को भी बीएसएनएल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के संयुक्त विरोध को दबाते हुए कब्जा कर लिया गया।

अब राष्ट्रीय पैमाने पर 531 परिसंपत्तियों की सूची जारी की गई है। यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि उस

सूची में शामिल किये जो कई परिसंपत्तियों की वास्तविक माप से कम दिखाई गई है तथा प्रस्तावित मूल्य भी बाजार दर से कम प्रतीत होते हैं। उस सूची में खाली पड़े भूमि, भवन, प्रशिक्षण केंद्रों तथा स्टाफ क्वार्टर को शामिल किया गया है। ज्ञातव्य है कि यह बिक्री नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत की जायेगी। अतः समस्त राजस्व भारत सरकार के वित्त विभाग को प्राप्त होगा।

बीएसएनएल में समायोजन के पूर्व यह आशंका जताई जा रही थी कि सरकार बीएसएनएल इसलिए बनाई है कि उसे निजी हाथों में दे दी जायेगी। परंतु सरकार द्वारा दिये गये लिखित वचन पर विश्वास करते हुए कर्मचारियों ने अपने को निगम में कार्य करने की सहमति दी और अत्यंत आसानी से दूरसंचार विभाग के दो विंग निगम में कर्मचारी सहित परिवर्तित हो गए।

इस स्थिति में कर्मचारी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कर्मचारियों की वाजिब एवं अधिकारिक मांगों को बिल्कुल अनसुनी करते हुए सरकार अपनी एजेंडा पर काम कर रही है। तृतीय वेतन संशोधन पर प्रतिरोध जारी है, आधे परिमंडलों में पदोन्नति की प्रतिस्पर्धा परीक्षाएं रिक्त नहीं होने के नाम पर आयोजित नहीं की जा रही है।

जहां तक कंपनी के नित्य कार्यों तथा संस्थापना, अनुरक्षण सहित उपभोक्ता सेवा केंद्रों सहित लगभग सभी कार्य निजी क्षेत्र के ठेकेदारों को सौंप दी गई है।

इस बीच बी एस एन एल प्रबंधन ने 1 3 2 करोड़ रुपये की लागत पर एक अमेरिकी कंपनी बोस्टन कंसलटेंसी ग्रुप को अनुबंध द्वारा नियुक्त किया है जो बीएसएनएल की सेवाओं, साज-समान, रखरखाव, कर्मचारी उपयोग उपभोक्ता सेवा केंद्रों आदि का अध्ययन करके आठ माह में अपनी अनुशंसा देगी। पता नहीं ये कौन सी कार्यवाही होगी और इससे इस खोखले हो चुके बीएसएनएल को क्या लाभ होगा इस पर प्रश्न चिन्ह है!

आज इस परिस्थिति को भांपकर बीएसएनएल के कर्मचारी यह कहने लगे हैं कि निगम बनाते समय जो कर्मचारियों के मन में भय था कि कुछ समय के बाद बीएसएनएल का निजीकरण कर दिया जायेगा वह आज सत्य प्रतीत हो रहा है।

इस परिस्थिति को भांपते हुए यह महसूस हो रहा है कि कर्मचारी हित में सभी कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों को एक साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और एकताबद्ध होकर कर्मचारियों के हित रक्षा के लिए अग्रसर कार्यवाही पर विचार करना चाहिए।

एनएफटीई (बीएसएनएल) हर वक्त एकताबद्ध प्रयास की पदाक्षर रही है। और आज भी हम पूरे मुस्तैदी के साथ कर्मचारी हित में संपूर्ण एकताबद्ध होकर अग्रसर होने की स्थिति में अगले कतार में रहेगी।

एनएफटीई जिंदाबाद
कर्मचारी एकता जिंदाबाद